सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 10 JULY TO 16 JULY 2020 • VOLUME- 44 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

No Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA

U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

*T&C apply

अवैध कालोनियों में राजीनामा योग्य निर्माण के गलत रेट लगाकर लोगों को किया जा रहा गुमराह

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

केन्द्र में प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की जिसको पंजाब की सरकार पहले से ही बखूबी से निभा रही थी और कोरोना महामारी के बाद और तेज़ी से निभा रही यह कोई काल्पनिक व्यंग्य नहीं इसकी हकीकत आप जब गहराई से जांच करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा।

पूर्व अकाली भाजपा सरकार द्वारा 2013 में पंजाब में चल रहे लैंड माफिया द्वारा काटी गयी कोलोनियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित उन कोलोनियों के निवासियों को राहत प्रधान करते हुए सभी कोलोनियों और प्लाटों को नियमित कराने के लिए एक मौका दिया और लोगों ने पूरी जिम्मेवारी के साथ सरकार द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार में उनके क्षेत्र फल के हिसाब से बनती धनराशि जमा करवाई और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया और जिन्होंने 2013 में इस योजना का लाभ नहीं लिया। अभी की मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने दोबारा पालिसी को लाकर अवसर दिया परन्तु सरकार ने लोगों से तो बनती राशि की वसूली कर ली लेकिन उसके मुलभुत सुविधाएं देने के वादे को भूल गयी और जो 5 प्रतिशत ज्यादा बिल्डिंग की कवरेज को राजीनामा का रेट उनके अफसर पालिसी से नहीं अपनी मर्जी से अपने द्वारा काटी गयी कोलोनियों के रेट पर जैसे की अर्बन एस्टेट के रेट पर उनको अवैध रूप से नोटिस भेज रही है।

यह एक गंभीर जांच का विषय है की जो करोड़ों रुपया सरकार ने वसूली की उसको कहाँ खर्च किया जो अब फिर अवैध रूप से लोगों की राजीनामा योग उसारी के गलत रेट को लगाकर क्यों आम जनता को इस कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में और सताया जा रहा है।

मकसूदां बिजली विभाग उड़ा रहा है स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां

नीरज की विशेष रिपोर्ट

प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 साल से प्रयास कर रहे है की भारत की छवि को विदेशों की तर्ज पर सुधारा जा सके जिसको सुधारने के लिए उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की जिसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई लोगों ने भी सहयोग करना शुरू किया परन्तु उनकी इस योजना को सरकारी विभाग ही विफल करने में लगे हुए जिसका एक उदाहरण मकसूदां बिजली विभाग की दयनीय हालत और जगह-जगह पर गंदगी देखकर खुद ही एहसास हो जायेगा की किस प्रकार प्रधानमंत्री की योजना को ठेंगा दिखाया जा रहा है अगर ऐसा कोई आम व्यक्ति करे तो उसके थूकने पर भी चालान है और कोरोना महामारी के दोर में ऐसी गंदगी किसी और बिमारी को भी दस्तक दे सकती है। लोगों को बिजली कैसे पूरी देंगे अफसर इनकी तो खुद के हालात वेंटीलेटर पर व्यक्ति समान है।

कानपुर से 17 किमी पहले एनकाउंटर में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ढेर

गैंगस्टर का गेम ओवर

- सुबह चार गोलियों ने खत्म की कहानी, शाम को कानपुर के विद्युत शवदाहगृह में हुई अंत्येष्टि
- अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए माता-पिता, शव लेने से भी किया इनकार, पत्नी और बेटा पहुंचे
- पुलिस पर भी चलेगा हत्या का केस, साबित करना होगा कि आत्मरक्षा में चलाई गोली

कानपुर ■ एजेंसी

कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे शुक्रवार सुबह 6.30 बजे भौंती क्षेत्र के पास पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर सुरक्षा बल कानपुर लेकर आ रहे थे कि भौंती क्षेत्र के पास वाहन पलट गया, जिससे पुलिस और एसटीएफ के चार जवान घायल हो गए।

आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन वह नहीं माना...

उन्होंने बताया कि तीन जवानों के घायल होते ही विकास ने एक जवान की पिस्टल लेकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने उसे घेर कर आत्मसमर्पण को कहा, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई जिसमें विकास घायल हो गया। उसे लाला लाजपत राय अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन शाम होते तक एसटीएफ ने अपना बयान बदल कर बताया कि बारिश से नहीं विकास की गाड़ी के सामने गाय-भैंस का झुंड आने पर गाड़ी को बचाने ड्राइवर ने गाड़ी को टकरा गई, जिससे गाड़ी पलट गई।

■ अंजाम सही लेकिन तरीके पर ऐतराज

विकास को मारे जाने को लेकर भले ही राजनीतिक घमासान मचा हो लेकिन आम लोगों दुर्दात के खात्मे से राहत महसूस कर रहे हैं, हालांकि मुठभेड़ के तौर-तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं है और कानून व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं मानते।

शुक्रवार देर शाम कानपुर के भैरव शमशान घाट पर विकास दुबे का पत्नी और अन्य परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

एनकाउंटर से कई राज दफन

प्रयागराज, (एजेंसी)। हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद हंडिया के शहीद पुलिसकर्मी नेबू लाल के परिजनों ने योगी सरकार की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी मृत्यु से कई राज दफन हो गए है। हंडिया के नब्बे चौराहा गांव निवासी शहीद उप निरीक्षक नेबू लाल बिंद कानपुर में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में मारे गए आठ पुलिस कर्मियों में से एक थे।

नहीं मिले इन सवालों के जवाब

- हादसे की वजह शाम तक बदल कैसे गई?
- विकास की गाड़ी के सामने ही कैसे आईं गाय-भैंस?
- गाड़ी में विकास के साथ पांच पुलिस वाले थे। सभी कुछ देर के लिए एक साथ अचेत कैसे हुए?
- विकास की गाड़ी से ठीक पीछे चल रही काफिले की गाड़ी इतनी दूर क्यों थी?
- इतनी देरी होने के बाद भी विकास ज्यादा दूर क्यों नहीं भाग पाया?
- आत्मरक्षा में पीछे से चलाई तीन गोलियां सीने पर ही कैसे लगीं?

पुलिस पर भी चलेगा हत्या का केस

- एनकाउंटर के तौर-तरीकों पर भी विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की कहानी अपनी जगह है, वहीं विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत केस तो हत्या का ही दर्ज होगा।
- समाजसेवी डा. नूतन ठाकुर ने विकास दुबे के मामले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत में कहा कि विकास का कृत्य जघन्य था, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने इसके बाद गैरकानूनी कार्य किए हैं, वह भी अत्यंत निंदनीय है।

मौके से पांच किमी पूर्व मीडिया को रोका

यूपी एसटीएफ विकास दुबे को सड़क मार्ग से लेकर निकली तो मीडिया की कई गाड़ियां एसटीएफ के काफिल के पीछे थीं। सुबह 3.15 पर झांसी बार्डरपर भी एसटीएफ ने रोकना चाहा। फिर सुबह 6:00 बजे के आसपास कानपुर देहात के बारा टोल प्लाजा पर काफिले के पीछे चल रहे मीडियाकर्मियों की गाड़ी को सचेंडी पुलिस थाने की पुलिस ने पांच किमी पूर्व रोक दिया।

विकास दुबे की पत्नी मीडिया पर बिफरी

कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मार गिराए जाने के बाद शाम को भैरवा घाट पर गैंगस्टर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उसकी पत्नी ऋचा ने जमकर गाली-गालौज की और कहा कि हां, उसके पति के साथ सही हुआ। पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आई पत्नी ऋचा से जब मीडियाकर्मियों ने सवाल पूछने शुरू किए, तब उसने अपना आपा खो दिया।

कोर्ट में दायर की गई थी पीआईएल

उप्र पुलिस द्वारा विकास दुबे के पांच सहयोगियों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पीआईएल दायर की गई थी। याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दाखिल करके दुबे को पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि मुठभेड़ के नाम पर पुलिस द्वारा आरोपियों को मारना कानून के शासन के खिलाफ है।

विश्व में क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का किया लोकार्पण

भोपाल/ रीवा ■ एजेंसी

- राज्यपाल आनंदीबेन एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से हुए शामिल
- सस्ती एवं साफ-सुथरी बिजली का हब बन रहा मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का निर्माण किया है। हमारे प्रयास है कि आम आदमी अपनी जरूरत की बिजली घर पर ही पैदा करे। इस कार्य में सरकार मदद करेगी। हम प्रयासरत है कि देश में बेहतर सोलर पैनल, बेट्री, स्टोरेज बनें तथा हमें विदेशों से उपकरण आयात नहीं करना पड़ें।

मप्र में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे है। मध्यप्रदेश सस्ती एवं साफ-सुथरी बिजली का हब बन रहा है। रीवा ने आज वाकई इतिहास रच दिया है। सफेद बाघ के नाम से जाना जाने वाला रीवा अब विश्व में सोलर प्लांट के नाम से भी जाना जाएगा। यहां खेतों में लगे हजारों पैनल ऐसा एहसास दिलाते हैं, मानो खेतों में फसल लहरा रही हो या गहरे समंदर का नीला पानी हो। इस अभूतपूर्व कार्य के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्र की जनता सहित पूरी टीम बधाई की पात्र है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हो रहे है। कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के साथ ही मप्र ने गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन किया है। अब मप्र सौर ऊर्जा उत्पादन में भी रिकार्ड बनाएगा। शासन ऐसी योजना बना रहा है, जिसके माध्यम से अब किसान अपनी बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकेगा। वह स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही दूसरों को भी बिजली दे पाएगा।

इंदौर में रिवाल्वर की नोक पर दिनदहाड़े बैंक में 5 .34 लाख रुपए की लूट

इंदौर, (आरएनएन)। उषानगर में डकैती की वारदात के तीसरे दिन शुक्रवार को परदेशीपुरा के एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 5.34 लाख रुपए की लूट की वारदात हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर 30 हजार का इनाम घोषित किया है। कई संदेहियों से पूछताछ की जा रही है।

तीन लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, 30 हजार का इनाम घोषित

फिल्मी स्टाइल में हुई इस वारदात के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। तीन शातिर लुटेरों ने रिवाल्वर की नोक पर चंद मिनटों में ही ये वारदात कर डाली। डाग स्कवाड एवं सीसीटीवी के फुटेज से लुटेरों की पहचान की जा रही है। एसपी विजय खत्री ने बताया कि शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस टीमें लुटेरों की तलाश में जुट गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।परदेशीपुरा चौराहे पर स्थित एक्सिस बैंक में जब नियमित कामकाज चल रहा था तभी तीन बदमाश बैंक में घुसे।

एक बदमाश के हाथ में रिवाल्वर थी। उसने सभी को धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी ने कोई आवाज की तो जान से मार देंगे। उसके बाद रिवाल्वर लहराते लुटेरा कैश काउंटर पर पहुंचा इस दौरान उसके साथी भी उसके साथ थे। लुटेरों ने रिवाल्वर की नोक पर कैश काउंटर से 5.34 लाख रुपए नकदी उड़ाए और वहां से फरार हो गए।

प्रसंग

छात्रों के लिए संगठित होने का समय

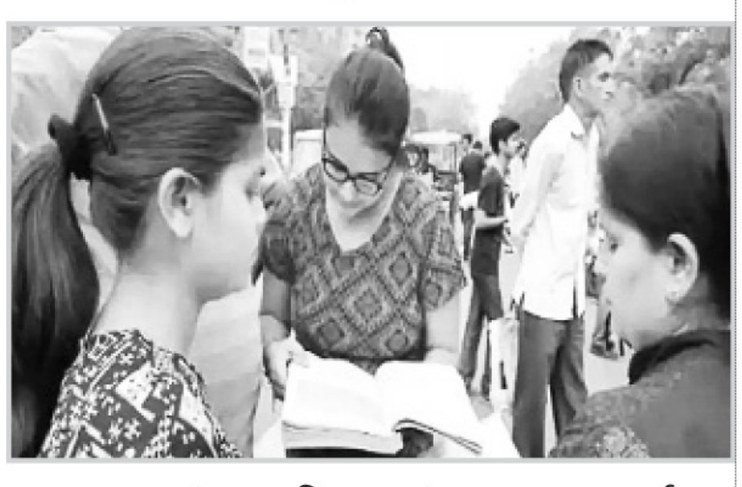

मानव संसाधन विकास मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे युवा शिक्षार्थियों के लिए सीखने की गुणवत्तामूलक प्रक्रिया को सशक्त बनाने और सहायता करने के लिए साहसिक निर्णय ले रहा है। शिक्षा को सिर्फ ज्ञान के प्रसारण मात्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसे छात्रों को सशक्त करने के एक ऐसे तंत्र के रूप में भी समझा जाना चाहिए जिससे वे आलोचनात्मक ढंग से सोच सकें, समस्याएं सुलझा सकें।

आधुनिक समय में किया जाने वाला अत्यधिक प्रचार केवल गलत सूचनाएं देने या एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं अपितु सत्य को मिटाने और आपकी समीक्षात्मक सोच को समाप्त करने के लिए किया जाता है। गैरी कास्परोव के इस उद्धरण ने हाल ही में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि किस प्रकार से विशेष रूप से सीबीएसई के छात्रों के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक सद्भावनापूर्ण कदम दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा बन गया। इस तरह के कृत्यों को देखते हुए हम हर बार शिक्षा को राजनीति से दूर रखने का प्रयास करते हैं, किंतु यह दुखद है कि शिक्षा हर बार इस तरह की तुच्छ राजनीति का शिकार होती है, जहां लोगों का एक निश्चित वर्ग, जिनको ऐसे निर्मम प्रचारकों के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, जो हमेशा सरकार की दूर-दृष्टि और कार्यों की भर्त्सना करने के साथ-साथ हमारे युवा शिक्षार्थियों के मन में अतिशय भय, भ्रम और कष्ट का कारण बनते हैं। वर्तमान में, लोगों का यह वर्ग छात्रों को 21वीं सदी के लिए सभी कौशलों के परिपूर्ण, नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा जैसी पूर्ण क्षमता के साथ सकारात्मक सोच, वैज्ञानिक स्वभाव, विश्लेषणात्मक शक्ति और रचनात्मकता रूप से सशक्त बनाने की बजाय अपने लिए प्रभुत्व और सत्ता पाने की भ्रांतिपूर्ण लालसा के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में देख रहा है।

इस अभूतपूर्व महामारी ने मंत्रालय के समक्ष यह चुनौती पेश की है कि सरकार छात्रों के लिए न केवल गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करे, बल्कि छात्रों के लिए एक तनाव-मुक्त वातावरण बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करे। इस दिशा में, मंत्रालय हमारे छात्र समुदाय से संबंधित सभी मुद्दों के प्रति जागरूकता अपनाते हुए संबंधित उपायों के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अवकाश के दौरान भी, बच्चों को मध्याह्न भोजन का प्रावधान, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की अगली कक्षा में प्रोन्नति, कक्षा 12 के छात्रों को 'चयन के अधिकार' देना और भारत में ई-लर्निंग को बढ़ावा देने जैसे अनुकरणीय निर्णयों को लेने और उनका समर्थन करने के लिए मैं मानव संसाधन विकास विभाग की टीम पर गर्व का अनुभव करता हूं। हालांकि, हाल ही में, सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के संशोधन को लेकर सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से प्रभावित आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। इन सभी झूठे आरोपों के बावजूद, हम मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी के शानदार नेतृत्व में आगामी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ निहित स्वार्थ से ग्रस्त लोग सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़ने और समझने की बजाय इसकी आलोचना कर रहे हैं।

यह क्या है और क्यों किया गया है छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए, सीबीएसई से पाठ्यक्रम को संशोधित करने और कक्षा 9 से 12 के छात्रों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने की सलाह दी गई थी। हालांकि पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम किया गया है परंतु यह सुनिश्चित करना विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों का दायित्व होगा कि कम किए गए विषयों को भी विभिन्न विषयों से जोड़ने के लिए आवश्यक जानकारी हेतु छात्रों को समझाया जाए। महामारी के कारण शिक्षा के समय की हानि के कारण, यह कदम 2021 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में छात्रों के लिए बोझ को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के तहत उठाया गया है। छात्रों का इन विषयों पर आंतरिक मूल्यांकन और वर्ष के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, हालांकि, सीबीएसई ने स्कूलों को एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करने के भी निर्देश दिये है। यह कैलेंडर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, और इसमें ध्यानाकर्षण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे सभी विषयों को इस कैलेंडर में शामिल किया गया है।

इस कैलेंडर में प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट शिक्षण योजना है जिसे आमतौर पर घरों में उपलब्ध संसाधनों की मदद से अनुभवात्मक या गतिविधि-आधारित शिक्षण के आधार पर जाना जा सकता है। जैसा कि मैं कहता हूं, 'शिक्षा से पहले सुरक्षा' इसलिए वास्तव में, ये उपाय छात्रों को होने वाली परेशानियों और तनाव को कम करने में मदद करेंगे और कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षाओं के लिए किया गया यह बस एक बार का उपाय है। युक्तिसंगतता की प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी इन तथाकथित प्रचार के भूखे लोगों द्वारा मानी जा रही है। हमारे सिलेबस-फॉर-स्टूडेंट्स-2020 अभियान के जरिए मिले सुझावों पर विचार करते हुए, जिसमें 1500 से ज्यादा विशेषज्ञों से सुझाव मिले और कई सारे विशेषज्ञों की सलाह और सिफारिशों के बाद एक बहुत कठोर कवायद को अंजाम दिया गया। शिक्षाविदों के सुझावों और विशेषज्ञता ने हमें सीखने के परिणामों को अक्षुण्ण रखते हुए न्यायपूर्ण युक्तिसंगतता लाने में मदद की है। राष्ट्रवाद, स्थानीय सरकार, संघवाद जैसे 3-4 विषयों को बाहर रखे जाने के विपक्ष के गलत बयानों के उलट, युक्तिकरण सारे विषयों में किया गया है। मिसाल के तौर पर, अर्थशास्त्र में ये अपेक्षित विषय हैं फैलाव के उपाय, भुगतान घाटे का संतुलन, आदि।

जबकि भौतिकी में ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, हीट ट्रांसफर, कनवेक्शन और रेडिएशन आदि हैं। इसी प्रकार गणित में निर्धारकों के गुण, संगतता, असंगतता व द्विपदीय संभाव्यता वितरण और उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरणों की प्रणाली के समाधानों की संख्या। जीव विज्ञान में खनिज पोषण, पाचन और अवशोषण के कुछ हिस्से आदि हैं जिनको मूल्यांकन से छूट दी गई है। ये तर्क कोई नहीं दे सकता है कि इन विषयों को किसी द्वेष भावना में या सोची समझी योजना के तहत बाहर रखा गया है, जो केवल कुछ पक्षपाती दिमाग ही समझ सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और युवा शिक्षार्थियों के लिए सीखने की गुणवत्तामूलक प्रक्रिया को सशक्त बनाने और सहायता करने के लिए एक साहसिक निर्णय ले रहा है। शिक्षा को सिर्फ ज्ञान के प्रसारण मात्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसे छात्रों को सशक्त करने के एक ऐसे तंत्र के रूप में भी समझा जाना चाहिए जिससे वे आलोचनात्मक ढंग से सोच सकें, समस्याएं सुलझा सकें, जिंदगी रोजाना जो भी चुनौतियां रखती जाएगी उनके बीच वे रचनात्मक होना, खुद को अनुकूलित करना और नवीन स्थितियों में सीखना ये सब कर सकें।

हम सबका ज्ञान-सबके लिए ज्ञान के विचार में विश्वास करते हैं और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए महज ज्ञान की संरचनाएं बना देने का विरोध करते हैं। हमें ऐसी ज्ञान व्यवस्था को महत्व देना चाहिए जो छात्रों को ऐसे सच्चे ज्ञान से सक्षम करे जो अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, सीखने वाले पर केंद्रित और रचनात्मक है। चर्चा छात्रों के विकास और सशक्तिकरण पर होनी चाहिए, न कि उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए और उस व्यवस्था का मखौल उड़ाने के लिए जो युवाओं की जिंदगी को सशक्त करती है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक सभी से निवेदन करता हूं कि रचनात्मक विचार-विमर्श और कार्यों के जरिए भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। आइए, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम सब मिल-जुलकर प्रयास करते हैं।

विचार

आखिर विकास का काम तमाम

विकास का अंत आज जिस अंदाज में किया गया है, उसकी चिंगारी कई दिनों तक उठेगी, जांच भी होगी। मगर इस कार्रवाई से यूपी सरकार ने यह संदेश तो दिया ही है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई से नि:संदेह दूसरे अपराधियों में डर पनपेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस के आठ जवानों की बर्बर हत्या का आरोपी विकास दुबे फिल्मी अंदाज में मारा गया। यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी। स्पीड तेज थी। बारिश होने से रोड पर फिसलन थी। पुलिस के मुताबिक, बर्रा के पास अचानक रास्ते में गाड़ी पलट गई। इस हादसे में विकास दुबे और एक सिपाही को भी चोटें आईं। इसके बावजूद विकास की नजरें पुलिस के चंगुल से बचकर भागने पर थी। मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इसी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एसटीएफ ने विकास दुबे से हथियार रखकर सरेंडर करने को कहा। नहीं माना तो पुलिस को मजबूरन एनकाउंटर करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचा था और वहां मंदिर के सुरक्षाकर्मियों को शक होने पर गिरफ्तार कर लिया था। उसे लगता था कि महाकाल की शरण में जाने से वह अकाल मृत्यु से बच जाएगा, लेकिन आज साफ हो गया है कि महाकाल भी अपराधियों को आशीर्वाद नहीं देते हैं। वैसे, इस एनकाउंटर की कहानी सभी को पहले से पता थी।

विकास को जब गुरुवार को उज्जैन में पकड़ा गया था, तब ही साफ हो गया था कि विकास की उम्र अब पूरी हो गई है। यूपी पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक ने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। खैर, विकास के मारे जाने का गम शायद ही किसी को हो। उसकी जैसी करतूत थी, उसमें उसका अंजाम ऐसा ही होना था। मगर उसे किसी तरह जिंदा रखा जाता तो शायद उन नाम को सामने लाया जा सकता था जो विकास जैसे अपराधियों को शह देते हैं। पुलिस की कार्रवाई पर शक सिर्फ इतनाभर है कि वह विकास से कानून व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे लोगों को बेपर्दा करा सकती थी। विकास से उज्जैन में पूछताछ में सामने आ चुका था कि उसे राजनीतिक संरक्षण के साथ कारोबारियों का भी साथ मिला। शहर से लेकर दिल्ली, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में उसको इन्हीं लोगों ने संरक्षण दिया। फरार करने में भी मदद की और एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में भी साथ देने में कसर नहीं छोड़ी।

बिकरू गांव में वारदात को अंजाम देने के बाद विकास कई नेताओं के भी संपर्क में रहा है। पूछताछ में भी जानकारी दी है। नाम भी बताए हैं। कानपुर पुलिस और एसटीएफ इस बारे में विस्तार से खंगाल रही है। यह सब आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। विकास को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। उसने दरिंदगी की जो हद पार की, उससे आज हर कोई खुश है। यूपी पुलिस ने जब तीन दिन पहले कहा था कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तभी तय हो गया था कि विकास जिस दिन हाथ आया, मारा जाएगा। विकास का अंत आज जिस अंदाज में किया गया है, उसकी चिंगारी कई दिनों तक उठेगी, जांच भी होगी। मगर इस कार्रवाई से यूपी सरकार ने यह संदेश तो दिया ही है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

हवा बच्चों को दे रही दिक्कत

दमघोटू हवा के मामले में भारत के हालात भयावह होते जा रहे हैं। हवा में घुल रही जहरीली गैसों के कारण सांस लेने के लिए स्वस्थ वायु महानगरों में ही नहीं दूर दराज के गांवों-कस्बों में भी नहीं बची है। बीते कुछ सालों में प्रदूषण के अत्यधिक खतरनाक स्तर की वजह से अब इंसानी डीएनए पर भी असर हो रहा है। वातावरण की ऐसी स्थितियां वाकई खतरा बन गई है। इतना बड़ा खतरा कि दुनियाभर में 10 फीसद बच्चे प्री-मेच्योर डिलीवरी से जन्म ले रहे हैं। कनाडा, चीन, जर्मनी, घाना और भारत जैसे देशों में शोध करने में जुटी जर्मनी की द पीफ्रोहेम आर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब जन्म से पहले ही दमघोटू हवा के नुकसान इंसान तक पहुंच रहे हैं जिससे भ्रूण में बदलाव आ रहा है। नतीजतन समय से पहले प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं।

वायु प्रदूषण को लेकर पहले से ही कई महानगरों में आपातकालीन स्थिति को झेल रहे भारत की स्थिति समय से पहले प्रसव के मामलों में भी बेहद चिंतनीय है। भारत में 15 फीसद बच्चे प्री-मेच्योर डिलीवरी से पैदा हो रहे हैं। भ्रूण में हो रहे बदलाव के कारण मेंटल डिस्ऑर्डर, दुबले-पतले, दिव्यांग या आंखों की समस्याओं के साथ बच्चे जन्म ले रहे हैं। ऐसी बीमारियों के साथ पैदा हो रहे बच्चे आगे चलकर भी स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं ने जूझते हैं। यह वाकई दुखद है कि हवा में घुले जहर के चलते नई पीढ़ी कई व्याधियों के साथ दुनिया में आ रही है है। इस मामले में बीते साल आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 'वायु प्रदूषण एवं बाल स्वास्थ्य-साफ हवा का नुस्खा' भी चेताने वाली थी। अध्ययन में कहा गया था कि वर्ष-2016 में भारत समेत निम्न एवं मध्यम आय-वर्ग के देशों में पांच साल से कम उम्र के 98 फीसदी बच्चे अतिसूक्ष्म कण (पीएम) से पैदा वायु प्रदूषण के शिकार हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2016 में एक लाख 10 हजार बच्चों की मौत की वजह लगातार प्रदूषित होती जा रही हवा रही है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भी भारत के आंकड़े सबसे ज्यादा थे। चिंतनीय है कि हमारे यहाँ साल-दर-साल प्रदूषण की स्थितियां और गंभीर होती जा रही हैं। एशिया के कई देशों में प्रदूषण रोकने की दिशा में काम करने वाली एयर एशिया नामक संस्था के एक शोध मुताबिक, दिल्ली में एक नवजात शिशु भी रोजाना परोक्ष तौर पर 15 सिगरेट का धुआं ग्रहण करता है। कोई हैरानी नहीं कि भारत में दुनिया के किसी भी स्थान की तुलना में श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण भी सबसे अधिक लोगों की मौत होती है। हालिया बरसों में

दमघोटू हवा के मामले में भारत के हालात भयावह होते जा रहे हैं। कुछ सालों में प्रदूषण के अत्यधिक खतरनाक स्तर की वजह से अब इंसानी डीएनए पर भी असर हो रहा है। दुनियाभर में 10 फीसद बच्चे प्री-मेच्योर डिलीवरी से जन्म ले रहे हैं। यह समस्या हमारे बच्चों से जुड़ी है। लिहाजा, हमें गंभीर होना पड़ेगा और देश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा।

बढ़ते औद्योगीकरण, कचरा जलाने और वाहनों की संख्या बढ़ने से भारत में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में तो हर साल स्थितियां आपातकालीन हो जाती हैं। ऐसे में हवा में बढ़ते प्रदूषण से बच्चों का न सिर्फ सांस लेना दुश्वार हो रहा है बल्कि सांस से जुड़े रोग भी बढ़ रहे हैं। इस हालिया अध्ययन के मुताबिक तो बच्चे गर्भ में ही कई बीमारियों का शिकार बन रहे हैं।

प्री-मेच्योर डिलीवरी के कारण अस्वस्थ और कमजोर बच्चे जन्म ले रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक, अत्यधिक प्रदूषण वाले कणों, जैसे एसिड, धातु व हवा में मौजूद धूल कणों के संपर्क में आने से भी समयपूर्व प्रसव का खतरा काफी बढ़ जाता है। दमा से पीड़ित गर्भवती महिलाओं में तो हवा के प्रदूषण के कारण निर्धारित समय से पूर्व प्रसव का खतरा 30 फीसदी तक बढ़ जाता है, जो महिलाएं दमे की शिकार नहीं हैं उनके लिए भी यह खतरा 8 प्रतिशत होता है। हालांकि, दमघोटू हवा के चलते हर उम्र के लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं मगर नई पीढ़ी के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी स्थितियां काफी भयावह हैं। यह चेताने वाली बात है कि देश के भविष्य को बचपन में ही अनगिनत बीमारियां घेर रही हैं। कई अध्ययन बताते हैं कि बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के मामलों की सबसे बड़ी वजह भी हवा में मौजूद हानिकारक तत्व ही हैं। इतना ही नहीं वायु प्रदूषण का गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके कारण जन्म के समय बच्चों में कई विकृतियां पैदा होने का भी खतरा है। शारीरिक या मानसिक दोष व कम वजन जैसी समस्याएं समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों में देखने को मिलती हैं। दरअसल, गर्भावस्था में महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक कम जाती है। ऐसे में हवा में मौजूद हानिकारक तत्व न केवल उन्हें बल्कि कोख में पल रहे बच्चे को भी व्याधियों का शिकार बनाते हैं। जन्म से पहले ही कई बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर तक हो जाता है। भ्रूण तक ऑक्सीजन का प्रवाह मां से ही होता है। ऐसे में अगर मां ही प्रदूषित हवा में सांस ले रही है तो फिर अजन्मे बच्चों में भी दूषित हवा के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंतनीय है कि भारत के महानगर तो प्रदूषण की गिरफ्त में हैं ही, दूसरे बड़े शहर और गांव-कस्बे भी दूषित हवा की भीषण चपेट में हैं। देश के हर भूभाग में प्रदूषणजनित स्वास्थ्य विकार तेजी से फैलते जा रहे हैं। खासकर वायु प्रदूषण तो दुनियाभर में मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

मौजूदा समय में हवा का विषाक्त होना पर्यावरण और सेहत से संबंधित दुनिया का अकेला सबसे बड़ा ख़तरा है, जो वैश्विक स्तर पर चिंता और सरोकार का विषय बन गया है। हमारे देश की स्थिति तो इस मामले में अति चिंतनीय है। हमारे परिवेश में फैली विषाक्त वायु को लेकर अब चिंता ना की गई तो शायद बहुत देर हो जाए। देश के मानव संसाधन और पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचा रही यह समस्या बच्चों के जीवन का भी लील रही है। यह दुखद और चिंतनीय है कि वायु प्रदूषण बड़े होते बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में तो रुकावट डाल ही रहा है और जन्म से ही उन्हें बीमारियों का शिकार भी बना रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी को आपातकालीन उपाय करने को कहा था।

यह तो और भी दुखद है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल से कम उम्र के 60 हजार 987 बच्चे पीएम 2.5 की वजह से मारे गए। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में करीब 20 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई है। दरअसल, दमघोंटू हवा के मामले में सभी महानगरों के हालात भयावह हो चले हैं। हवा में घुल रही जहरीली गैसों के कारण सांस लेने के लिए स्वस्थ वायु नहीं बची है।

देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए इलाके तो प्रदूषण के अत्यधिक खतरनाक स्तर को झेल रहे हैं। हालिया बरसों में न्यायालय ने भी जहरीली होती हवा को लेकर कई बार चिंता जताई है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच एक अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन के विश्व के तीन सबसे बड़े हॉटस्पॉट भारत में हैं। अब भी कुछ सोचने को बचा है।

ट्विटर

अपराधी का अंत हो गया, उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? योगी सरकार को इसका जवाब देना होगा। विकास को ढेर कर पुलिस ने कई सवालों को दफन कर दिया।

प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

दरअसल कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। योगी सरकार विकास को मार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर वह सवालों में उलझ गई है।

अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

सत्यार्थ

संतों की जरूरत

एक दिन नामदेव से उनकी मां ने कहा- बेटा, जरा दवा बनाने के लिए आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी छाल उतार लाओ। मुझे एक जरूरी दवा बनाने के लिए उसकी जरूरत है। मां का आदेश मिलते ही नामदेव आंवले के वृक्ष की खोज में निकल पड़े। कुछ देर बाद जब वे आंवले के पेड़ की छाल उतार कर लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले। नामदेव ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा- नामदेव, यह क्या है? नामदेव ने कहा- दवा बनाने के लिए आंवले के वृक्ष की छाल उतार कर लाया हूं। महात्मा ने कहा- क्या तुम्हें पता नहीं कि हरे पेड़ को क्षति पहुंचाना अधर्म है। वृक्षों में भी तो जीवन होता है। इन्हें देवता मान कर पूजा जाता है। वैद्य जब किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ते हैं, तो पहले हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं कि दूसरों के प्राण बचाने के उद्देश्य से ही आपको यह कष्ट दिया जा रहा है। यह हमारी संस्कृति का विधान है। नामदेव इस बात से बहुत प्रभावित हुए। घर जाकर उन्होंने छाल मां को दे दी और एक कमरे के कोने में बैठकर चाकू से अपने पैर की त्वचा छीलने लगे। उनके पैर से खून बहते देखा, तो मां ने पूछा-तू यह क्या कर रहा है? नामदेव बोले कि महात्मा ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है। मैं पैर की त्वचा उतारकर देख रहा हूं कि क्या त्वचा उतारने में दर्द होता है? यह सुनकर मां ने बेटे को छाती से लगा लिया। वे समझ गईं कि उनके बेटे पर सत्संग के विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। आगे चल कर तो नामदेव खुद ही संत बन गए। उन्होंने कण-कण में भगवान के दर्शन किए हैं। सचमुच, अब नामदेव जैसे संतों की ही जरूरत है, जो कि पर्यावरण का महत्व समझ सकें एवं दूसरों को भी समझाकर हरे-भरे वृक्षों को कटने से रोक सकें।

विकास एनकाउंटर मामले में एमपी की राजनीति गरम

भोपाल,(रासं) । उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश और आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद मध्यप्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष से भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के अलावा भाजपा की दिग्गज नेत्री और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से तीन सवाल किए हैं। उन्होंने विकास दुबे के उज्जैन आने और आसानी से गिरफ्तार होने पर सवाल उठाए।

दिग्विजय सिंह ने की विकास दुबे के मामले में न्यायिक जांच की मांग

भोपाल, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। श्री सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि विकास दुबे ने उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए क्यों चुना। मप्र के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने आया था। मैं शिवराज जी से विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर की न्यायिक जांच की मांग करता हूं। इस कुख्यात गेंगस्टर के किस किस नेता व पुलिसकर्मियों से संपर्क हैं जांच होना चाहिए। विकास दुबे को न्यायिक हिरासत में रखते हुए इसकी पुख्ता सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि सारे राज सामने आ सकें।

विकास दुबे को लेकर उमा भारती ने दागे तीन सवाल

भोपाल। वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने विकास दुबे एनकाउंटर पर ट्वीटर के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देवेंद्र मिश्रा जैसे ईमानदार डीएसपी एवं उनके साथ आठ पुलिस अफसर व सिपाहियों की निर्मम हत्या करने वाले राक्षस विकास दुबे को मार गिराने के लिए यूपी पुलिस को बधाई, यूपी पुलिस की जय हो। अभी भी उसने भाग निकलने की चेष्टा की, किंतु वह मार गिराया गया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से इस पर बात अवश्य करूंगी, किंतु सच्चाई तो सामने आ गई कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्रा जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया। अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अब तीन बातें रहस्य की परत में हैं-(1) वह उज्जैन तक कैसे पहुंचा? (2) वह महाकाल परिसर में कितनी देर रहा? (3) उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई पहचान लेता तो उसको पहचानने में इतना समय कैसे लगा ?

गैंगस्टर का साम्राज्य समाप्त

08 जुलाई
एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस के संयुक्त आपरेशन में विकास का 50 हजार का इनामी भतीजा अमर दुबे मौदहा में मारा गया।

09 जुलाई
विकास दुबे के दायें हाथ माने जाने वाला साथी प्रभात कानपुर में और 50 हजार का इनामी प्रवीण दुबे उर्फ बउआ मुठभेड़ में ढेर

10 जुलाई
कानपुर से 17 किमी पहले सचेंडी थाना क्षेत्र में सुबह 6.30 बजे एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत

06 जुलाई
अपराधी के मददगार दो दरोगा निलंबित, विकास के भतीजे की पत्नी , नौकरानी और पड़ोसी गिरफ्तार किए गए।

05 जुलाई
कल्याणपुर मुठभेड़ में पकड़े गए विकास के गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री ने उगले कई राज। पुलिस की 60 टीमें तलाश में जुटीं ।

04 जुलाई
पुलिस ने दो बीघा जमीन पर बने हिस्ट्रीशीटर का किलेनुमा घर को जमींदोज कर दिया। लग्जरी कारों का बेड़ा तबाह किया।

03 जुलाई
पुलिस ने दुर्दांत अपराधी के मामा प्रेम प्रकाश पांडेय और चचेरे भाई अतुल को बिकरू से 10 किमी दूर मुठभेड़ में किया।

मध्यप्रदेश पुलिस के सामने पांच सवाल

1- पुलिस के अलर्ट पर होने के बावजूद विकास दुबे एमपी में कैसे प्रवेश किया?

2-एमपी के कई जिलों से निकला, लेकिन चैकिंग व्यवस्था होने के बाद भी क्यों नहीं पकड़ा गया?

3- एमपी में विकास दुबे सफर करता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस को क्यों नहीं मिला इनपुट?

4- महाकाल मंदिर परिसर में प्रवेश के दौरान पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ा?

5-विकास दुबे के संपर्क में रहने वाले बदमाशों और मददगारों की क्यों नहीं की गई निगरानी?

मध्य प्रदेश पुलिस का जांच में रोल : यूपी पुलिस के डायरेक्शन में एमपी पुलिस काम करेगी। फिलहाल अभी एमपी पुलिस को इस केस की जांच का कोई निर्देश नहीं मिला है।

प्रदेश सरकार खुलासा करे विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा: कमलनाथ

भोपाल, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को एक बार फिर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को यह खुलासा करना चाहिए कि गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि भगवान महाकाल कभी किसी पापी को बख्शते नहीं, यह मैंने गुरुवार को भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि महाकाल की नजरों से कोई भी पापी नहीं बचेगा। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हुआ, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित है। जिस दुर्दांत अपराधी को पुलिस की 40 टीमें खोज रही हो वो इनामी बदमाश सुरक्षित यूपी रजिस्टर्ड कार से उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। वो उज्जैन कितने दिन रहा, किसके संरक्षण में रहा। उसके साथ कितने साथी थे, वो कहां है।

जिसका अनुमान जताया गया था, वही हुआ: अजय सिंह

भोपाल, (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने उप्र के कुख्यात गैंगेस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, वही हुआ। श्री सिंह ने यहां जारी बयान में कहा कि सवाल इस बात का नही है कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ, सवाल इस बात का है कि इस एनकाउंटर के बाद वो चेहरे कैसे बेनकाब होंगे, जो विकास को संरक्षण देते थे। यह शर्मनाक है कि आठ पुलिसकर्मियों का नरसंहार करके कोई अपराधी अपने राज्य की सीमा को पार कर जाता है और दूसरे राज्य में बड़े ही आराम से टहलता हुआ पाया जाता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि विकास मप्र की सीमा में कैसे आया और उसने अपने आपको बड़े ही नाटकीय ढंग से कैसे सुपुर्द कराया, ये ऐसे सवाल हैं, जो न केवल अनुत्तरित हैं, बल्कि उनका जवाब हर व्यक्ति चाहता है।

मध्यप्रदेश पुलिस ने अपना कार्य किया: नरोत्तम मिश्रा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार सुबह उज्जैन में पुलिस की अभिरक्षा में आए विकास दुबे को देर शाम पुलिस ने उत्तरप्रदेश पुलिस को सौंपने के बाद पूरे काफिले को सुरक्षित मध्यप्रदेश से उत्तरप्रदेश की सीमा तक पहुंचाया था। श्री मिश्रा ने यहां मीडिया के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने पर कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने के संबंध में श्री मिश्रा ने कहा कि यही लोग गुरुवार को उसके जिंदा पकड़े जाने पर सवाल उठा रहे थे और अब शुक्रवार को उसके मरने पर सवाल उठा रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि दरअसल संपूर्ण मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने अपना कार्य बेहतर ढंग से किया। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि वो दो दिन से उज्जैन में था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कार्य सिर्फ ट्वीट करना बचा हुआ है। उन्हें अब कोई जनसभा में बुलाता नहीं है। तो वे ट्वीट करके ही अपना कार्य करते हैं।

भाजपा नेताओं की पहले जुबान फिसली, बाद में किया सुधार

जल संसाधन मंत्री सिलावट बोले, पीएम-सीएम समाज का कलंक

इंदौर(आरएनएन)। कानपुर हत्याकांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इंदौर में भाजपा के मंत्री और सांसद ने बयान देते समय ऐसी बातें कह दी जो कि दिनभर चर्चा का विषय बनी। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समाज का कलंक कह दिया, वहीं सांसद शंकर लालवानी ने एनकाउंटर में मारे गए बदमाश का नाम संजय दुबे जी कह दिया। दोनों ही बयानों में शाम को सुधार करते स्पष्टीकरण के वीडियो जारी किए गए।

सांसद बोले, कानपुर हत्याकांड का आरोपी संजय दुबे जी

गुरुवार को उज्जैन से गिरफ्तार यूपी के आठ पुलिस अधिकारियों के हत्यारे विकास दुबे का यूपी पुलिस ने कानपुर के पहले एनकाउंटर किया। इस मुद्दे पर बयान देते हुए मंत्री सिलावट ने विकास दुबे को समाज का कलंक कहने के बजाए प्रधानंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए समाज का कलंक कह दिया। शाम को इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि विकास दुबे गुंडा था और समाज के लिए कलंक था। मैंने पीएम और सीएम को धन्यवाद दिया था। कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया है। इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करूंगा। वही सांसद शंकर लालवानी आरोपी को संजय दुबे जी कह गए। उन्होंने भी कहा कि मेरे एक कार्यकर्ता का नाम संजय दुबे है और उनका नाम लेते हुए सम्मान से दुबेजी कहते हैं। ऐसे में विकास दुबे के बजाय संजय दुबे नाम कहने में आ गया था।

पुलिस को अब है विकास के बचे 12 गुर्गों की तलाश

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चौबेपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के मारे जाने के बावजूद पुलिस की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस अब उन बचे हुए 12 शातिरों की तलाश कर रही है, जिन्होंने बिकरू गांव में दो जुलाई की रात दुस्साहिक वारदात को अंजाम दिया था। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा कि बिकरू कांड को अंजाम देने के मामले में 21 अभियुक्तों को नामजद किया गया था जबकि 60 से 70 अन्य अभियुक्त भी पुलिस के राडार पर है। उन्होंने बताया कि विकास दुबे समेत छह नामजद अभियुक्तों को अब तक ढेर किया जा चुका है, जबकि तीन को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि अब 21 में से 12 शातिर अब भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। अन्य अभियुक्तों में आठ को गिरफ्तार किया गया है। आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास को गुरुवार को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे लेकर कानपुर आ रहे थे कि भौंती के निकट पुलिस का वाहन पलट गया। इस बीच विकास ने एक घायल जवान की पिस्टल लेकर पुलिस बल पर गोली चलाई, जिससे चार पुलिस जवान और दो एसटीएफ के जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।

राहुल और प्रियंका ने विकास दुबे मुठभेड़ पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि आपराधिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक गठबंधन की असलियत सामने आये। श्री गांधी ने कहा कि शुक्रवार को सुबह हुई इस मुठभेड़ के साथ ही कई सवाल भी दफन हो गए है। उन्होंने ट्वीट किया कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बदतर हो चुकी है। राजनेता-अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की संठगांठ खुलकर सामने आई। कौन-कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं- ये सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस बीच पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां संवाददाता से कहा कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश में अपराध का एक मोहरा मात्र था।

विकास दुबे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो

लखनऊ, (एजेंसी)। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कानपुर पुलिस हत्याकांड और दुर्दात अपराधी विकास दुबे को मारे जाने की घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानपुर पुलिस हत्याकांड तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दान्त विकास दुबे को मप्र से कानपुर लाते समय शुक्रवार को पुलिस की गाड़ी के पलटने एवं उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराने आदि सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह उच्च-स्तरीय जांच इसलिए भी जरूरी है, ताकि कानपुर नरसंहार में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को इंसाफ मिल सके।

सीएम ने वीसी के जरिए रीवा अल्ट्रा सोलर पॉवर प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित

मोदी की प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहा है मप्र

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मैन ऑफ आइडियास' बताते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा और दूरदृष्टि से ही हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने वीसी के जरिए रीवा अल्ट्रा सोलर पॉवर प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली से जुड़े और उन्होंने संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही यह जान लिया था कि भविष्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा है तथा इस क्षेत्र में प्रभावी कार्य प्रारंभ कर दिए थे।

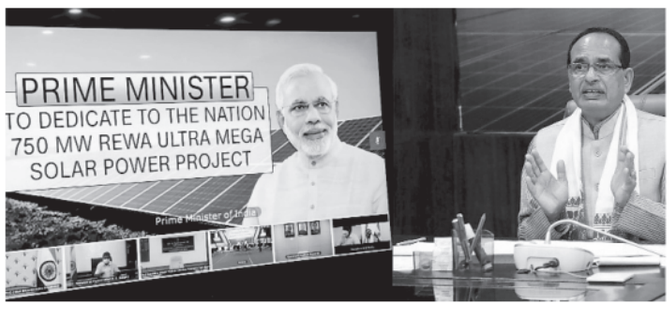

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लोकार्पण के अवसर पर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत जानकारी दी।

वर्ष 2010 में सौर ऊर्जा के लिए बनाया नया विभाग : श्री चौहान ने कहा कि मप्र में वर्ष 2010 में सौर ऊर्जा के लिए नया विभाग बनाया गया। एशिया की सबसे बड़ी सोलर इकाई का नीमच में शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा ही पहले किया गया था। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही वर्ष 2017 में रीवा सोलर प्लांट का कार्य केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। उन्होंने राज्य की सवा सात करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। श्री चौहान ने कहा कि रीवा सोलर प्लांट ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 'गेम चेंजर' परियोजना है। मात्र 2.97 रुपए प्रति यूनिट की सस्ती बिजली, प्रथम बार राज्य के बाहर व्यावसायिक संस्थान को बिजली प्रदाय करना, विश्व बैंक से बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना, दो करोड़ साठ लाख पेड़ों के बराबर कार्बन उत्सर्जन बचाना आदि ऐसे प्रतिमान हैं, जो इस परियोजना को अनूठा बनाते हैं।

मध्यप्रदेश निभाएगा बड़ी भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2022 तक देश में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश बड़ी भागीदारी निभाएगा। प्रदेश में आगामी सौर परियोजनाओं के जरिए लगभग 10 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होगी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार: श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की योजना को मूर्त रूप देने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार कर लिया गया है तथा उस पर तत्परता से अमल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीबों के लिए सराहनीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश के 14 जिलें इसमें शामिल किए गए हैं। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में चंबल एक्सप्रेस-वे के जरिए प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इसके लिए पूरा प्रदेश हृदय से आभारी है।

प्रधानमंत्री ने की सराहना: प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और अन्य कार्यों की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री के वक्तव्य को ध्यान से सुना और अंत में ताली बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन, स्वागत भाषण एवं आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने किया।

रेरा में प्रोजेक्ट पंजीकरण के आवेदन होंगे अब ऑनलाइन जमा

भोपाल, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के चलते मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में परियोजना के प्रमोटर को प्रोजेक्ट पंजीकरण का आवेदन पत्र रेरा वेब एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। रेरा द्वारा परीक्षण करने के लिए प्रमोटर को मात्र पांच आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कॉपी ही जमा करनी होगी। शेष दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा होंगे।

रेरा में प्रमोटर को आवेदन पत्र के साथ हार्ड कॉपी के रूप में जो पांच दस्तावेज जमा करने होंगे, उनमें खसरा (फॉर्म बी 1) की जेरॉक्स की सत्यापित प्रति, नई परियोजना के लिए शपथ पत्र की मूल प्रति, शपथ-पत्र सह घोषणा (फॉर्म बी) की मूल प्रति या आवेदन में आवश्यकतानुसार कोई अन्य शपथ-पत्र देना शामिल है। साथ ही ए-3 आकार के कागज में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत ले आउट प्लान और सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत भवन प्लान के सत्यापित दस्तावेज ही प्रस्तुत करना होगा। अन्य किसी अभिलेख की हार्ड कॉपी प्राधिकरण में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन दस्तावेज ही पर्याप्त होंगे।

'तू बहुत होशियार बन रहा, देख लूंगा'

भोपाल, (रासं)। प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें विधायक वन विभाग के रेंजर को एक मामले पर अपने कार्यकर्ता को छोड़ने की बात कर रहे हैं और इस बीच दोनों के मध्य तू तू मैं मैं के हालात भी निर्मित होते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में विधायक कह रहा है 'तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, तू बहुत होशियार बन रहा है'।

विधायक का रेंजर से तू-तू मैं-मैं का ऑडियो वायरल

भाजपा के जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का यह ऑडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोधी नौरादेही अभयारण्य के एक रेंजर तिलक सिंह रामपुरिया से एक व्यक्ति को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में ही विधायक द्वारा रेंजर से उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की बात कही जा रही है। साथ ही पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ने कहा जा रहा है, लेकिन वन विभाग के रेंजर द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को नहीं छोड़ने की बात कही जा रही है। दोनों के बीच काफी देर तू तू मैं मैं होती रही और वहीं विधायक वन विभाग के रेंजर के खिलाफ धरना देकर विरोध करने एवं कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं, तो रेंजर भी दबंगई के साथ कार्यवाही करवाने की बात कर रहा है।

आज ग्वालियर एवं मुरैना के प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री

विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सुबह भोपाल से ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर 11.50 पर ग्वालियर पहुंचेंगे तथा वहां दोपहर 12 बजे जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप के साथ बैठक कर कोरोना नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्री चौहान दोपहर एक बजे कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। श्री चौहान दोपहर 3 बजे स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 3.30 बजे मुरैना के लिए प्रस्थान कर 3.55 पर मुरैना आएंगे तथा वहां 4 बजे नगरीय पथ व्यवसायियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वे 4.45 पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ कोरोना संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे, शाम 6 बजे मुरैना से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे तथा 6.25 बजे ग्वालियर से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

कमलनाथ के कारण ही शिवराज मुख्यमंत्री बने : प्रद्युम्न

हमारे लिए विभाग नहीं, पहली प्राथमिकता जनसेवा

ग्वालियर (रासं)। प्रदेश में शिवराज सिंह की अगुवाई में जो सरकार बनी है, उसका कारण ही कमलनाथ हैं। अगर उन्होंने ग्वालियर-चंबल के विकास के प्रति ध्यान दिया होता तो उप चुनाव का समय ही नहीं आता, लेकिन उनको तो सिर्फ छिंदवाड़ा दिखाई दे रहा था। यह बात कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को अम्मा महाराज की छत्री में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहीं।

कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि हमारे लिए सत्ता नहीं, बल्कि उसके जरिए जनसेवा महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचे इसके लिए हम काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दिन-रात इसी काम में लगे हुए है। ग्वालियर का स्वरूप पुनः भव्यता प्रदान करे और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो इसी काम में भाजपा सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री भी शनिवार को इसी काम पर नजर डालने के लिए ग्वालियर आ रहे हैं। विभाग बंटवारे में हो रही देरी पर मंत्री तोमर ने कहा कि यह सीएम का विशेषाधिकार है। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि हमें फलां विभाग ही मिले। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ग्वालियर के विकास का पहिया रोक दिया था। कमलनाथ 15 माह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय तो एक बार भी ग्वालियर आने का समय नहीं मिला और अब उपचुनाव प्रचार के लिए हेड कर्वाटर बनाकर यहां रहेंगे तो जनता सब जानती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

ग्वालियर प्रवेश पर समर्थकों ने किया स्वागत: मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रद्युम्न सिंह शुक्रवार को बाई रोड ग्वालियर आए। इस दौरान समर्थक पनिहार टोल नाके पर ही स्वागत करने के लिए पहुंच गए। सिंधिया समर्थक सुरेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, श्याम सिंह चौहान, पुरुषोत्तम भार्गव सहित सैकड़ों लोग टोल नाके पर पहुंच गए और जैसे ही मंत्री का काफिला आया उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया।

ओपीएस बोले चुनौती स्वीकार करना हमारा स्वभाव

ग्वालियर,(रासं)। शिवराज सरकार में राज्यमंत्री बनाए गए सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया शुक्रवार को ग्वालियर आए। वे यहां थीम रोड स्थित सिंधिया राजवंश की छत्री पर पहुंचे और राजमाता विजया राजे सिंधिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया की मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री भदौरिया ने कहा कि जो संकल्प हमने राजमाता जी और बड़े महाराज साहब के सामने लिया था, जिनकी प्रेरणा से हम राजनीति में आए, मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। उपचुनाव में जीत की चुनौती पर भदौरिया ने कहा कि चुनौती स्वीकार करना हमारे स्वभाव में है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जनता एक बार फिर हमें समर्थन देगी। विभागों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वरिष्ठ नेतृत्व का मामला है मुझे उम्मीद है एक-दो दिन में निर्णय हो जाएगा। ओपीएस भदौरिया भिंड जिले से कांग्रेस विधायक थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए थे। वे पिछले दिनों ही राज्यमंत्री बनाए गए हैं और उन्हें उप चुनाव में उतरना है।

पार्षद तरसेम सिंह लखोतरा और उनकी समिति द्वारा स्वछता अभियान चलाया गया

छाया : रवि

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

वार्ड नंबर 34 के पार्षद तरसेम सिंह लखोतरा सत गुरु कबीर वेलफेयर कमेटी ने आज अपनी कमेटी के सभी साथियो के साथ मिलकर भार्गव नगर बूढा मल पार्क में सफाई की ओर से कहा की हमारी समिति हर रविवार को पार्क की सफाई करेंगी जब तक पार्क पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता और हमारी समिति भार्गव नगर के निवासियों को निवेदन करती है की इस अभियान में हमारा साथ दें और पार्क को गंदा ना करें।

इस मौके पर समिति के मुख्य सदस्य पार्षद तरसेम सिंह लखोतरा, यश पाल, राजू भगत, विजय कुमार, पुशपिनदर, सनी भगत, सतीश और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर पार्क की सफाई करने में हमारी मदद की और पार्षद तरसेम सिंह लखोतरा ने अपने सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त किया।

सत गुरु कबीर सेना की और से भार्गव नगर के निवासियों को मास्क बाँटे गए

जालंधर ब्रीज ब्यूरो

सत गुरु कबीर सेना ने मास्क लगाओ अभियान की शुरुआत की उन्होंने भार्गव नगर के निवासीयों को मास्क बाँटे, जिस में उन्होंने ने रेहड़ी व रिक्शा वालो को भी मास्क पहनाए । इस महामारी से बचने का सुझाव भी दिया और कहा की हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए अपना मुँह मास्क से ढकना चाहिए और हाथो को बार -बार सेनिटीज़र करना चाहिए इस अवसर पर विजय मिंटू, संजीव भगत, अमित भगत, मोहित बगत, सुदेश भगत, अमृत भगत, रवि, नीकु भगत, परवीन भगत, नितिन भगत, गुरमीत विक्की, टीटू, अमित, वीने भगत शिव भगत व अन्य मौजूद थे ।

डी.सी. जिले में शराब की समगलिंग विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए

जिलाधीश ने आबकारी और जीऐस्टी संग्रह की समीक्षा की

जालंधर/नीरज

डिप्टी कमिशनर श्री घनश्याम थोरी ने आज आबकारी विभाग को जिले में किसी भी तरह की शराब तस्करी खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए। जिला प्रशासकीय कंपलैक्स में यहाँ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश ने कहा कि इससे सख्ती के साथ पूरा किया जायेगा और दोषियों खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री थोरी ने कहा कि ऐसी कार्यवाहियों में शामिल व्यक्तियों खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए जिसमें आपदा प्रबंधन और महामारी सम्बन्धित एक्ट अधीन शामिल हैं। श्री थोरी ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में शराब की तस्करी और नाजायज शराब की बिक्री को रोकने के लिए विषेश चैकिंग का प्रबंध किया जाना चाहिए।

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि इस मंतव्य के लिए तहसील और सब डिविज़नल में आबकारी विभाग के साथ सिविल और पुलिस प्रशासन की सांझी टीमों की तरफ से ठोस प्रयत्न किये जाने की जरूरत है। श्री थोरी ने कहा कि ऐसीं किसी भी गैर कानूनी कार्यवाही के साथ सख्ती के साथ पूर किया जाना चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर श्री जसबीर सिंह और आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

अल्पसंख्यक वर्ग की शिकायतें / मुश्किलें निर्धारित समय के अंदर हल हों-साधु सिंह धर्मसोत

चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की विभिन्न तरह की शिकायतों/ मुश्किलों का हल निर्धारित समय-सीमा के अंदर किए जाने की जरूरत है, जिससे उनको न्याय मिलने में देरी न हो। आज यहाँ पंजाब भवन में पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के साथ की गई मीटिंग के दौरान स. धर्मसोत ने आयोग से अपील की कि वह राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित लोगों की शिकायतें / मसले तेजी से हल करने को प्राथमिकता दें।

धर्मसोत द्वारा पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के साथ मीटिंग

उन्होंने कहा कि आज के समय में भी अल्पसंख्यकों पर कई किस्म के दबाव डाले जाते हैं, जिनको सख्ती से रोके जाने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि चाहे कानून अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है, फिर भी कमज़ोर वर्गों के मसले पहल के आधार पर हल करना राज्य सरकार की प्रमुखता है। स. धर्मसोत ने आयोग द्वारा उठाई गईं विभिन्न माँगों और अन्य मसलों को पहल के आधार पर हल करने का भरोसा दिया।

इस मीटिंग में पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्रो. ईमैनुअल नाहर, सीनियर वाइस चेयरमैन मुहम्मद रफी, वाइस चेयरमैन हंस राज, कानूनी सलाहकार एंजलीना बराड़, सामाजिक न्याय, अधिकारता एवं अल्पसंख्यक विभाग के डायरैक्टर दविन्दर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा पंजाब में कोविड के केस बढ़ने के कारण प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की मंज़ूरी

राज्य सरकार द्वारा कल से पाँच जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का पायलट प्रोजैक्ट शुरू करने की तैयारी

चंडीगढ़/ब्यूरो

राज्य सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित पाँच जिलों में शुक्रवार से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का पायलट प्रोजैक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है और इसी दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज कोविड प्लाज्मा थैरेपी के इलाज की सुविधा के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने को हरी झंडी दे दी है। हालाँकि, आई.सी.एम.आर. के ट्रायल प्रोजैक्ट के तौर पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्लाज्मा थैरेपी से इलाज पहले ही किया जा रहा है।

राज्य में कोविड की स्थिति संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये हुई जायजा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ब्लॅड बैंक और ट्रांसफ्यूज़न मैडिसन के पूर्व प्रमुख डॉ. नीलिमा मरवाहा की निगरानी और मार्गदर्शन अधीन प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की मंज़ूरी दे दी है। डॉ. मरवाहा पहले ही इस प्रक्रिया में शामिल हैं और प्लाज्मा थैरेपी ट्रायल संबंधी अवगत करवा रहे हैं। प्लाज्मा बैंक गंभीर बीमार रोगी या गंभीर बीमारी के जोख़िम वाले लोगों के लिए तैयार सप्लाई स्रोत के तौर पर काम करेगा और इससे कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा से मरीज़ों का बड़े पैमाने पर इलाज किया जा सकेगा।

मीटिंग के दौरान बताया गया कि इस ट्रायल के लिए कुल 15 मरीज़ भर्ती किए जा चुके हैं, जिनमें से आठ को प्लाज्मा दिया गया है, जबकि बाकी 7 को आई.सी.एम.आर. की रैंडम विधि के मुताबिक निगरानी अधीन रखा गया है। पाँच मरीज़ पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, जिनको जल्द ही घर भेज दिया जाएगा। ठीक हुए 300 मरीज़ों में से अब तक 11 व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान किया है।

राज्य में सुरक्षा नियमों के बढ़ रहे उल्लंघन जिनमें से बहुत से राजनैतिक पार्टियों से हैं, पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही सभी राजनैतिक पार्टियों के मुखियों को पत्र लिखकर बड़े जलसे करने से गुरेज़ करने के लिए उनके सहयोग की माँग करेंगे।

मुख्यमंत्री ने अपील की कि वह राजनैतिक पार्टियों के नुमायंदों को कोविड के फैलाव का कारण बनने वाली किसी भी कार्यवाही से बचने के लिए भी अपील करेंगे। इस दौरान डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने कोविड से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर राजनैतिक पार्टियों के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए हैं और उनका विभाग भी सभी राजसी पार्टियों को ऐसे काम न करने के लिए पत्र लिखने की योजना बना रहा है।

मीटिंग के दौरान बताया कि बुधवार को 258 मामले सामने आए हैं और अब तक 11 पी.सी.एस. अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिनमें सी.एम.ओ. संगरूर, जॅज आदि शामिल हैं, भी कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसको आगे बढ़ने से रोकने की जरूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि दफ्तरी स्टाफ को विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है।

उन्होंने मुख्य सचिव विनी महाजन को सरकारी अधिकारियों

महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सभी राजसी पार्टियों के मुखियों को राजनैतिक जलसे करने से गुरेज़ करने के लिए पत्र लिखेंगे

की मीटिंगों, अन्य दफ्तरों में जाने आदि संबंधी निर्धारित संचालन विधि (एस. ओ.पी.) जारी करने के लिए कहा। यह स्पष्ट किया जाए कि लापरवाही वाले रवैए के कारण बहुत ही अहम मानवीय शक्ति के दरमियान रोग का फैलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा नियमों को सख़्ती से लागू किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब पुलिस प्रमुख को उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ चालान काटने में किसी प्रकार की नरमी न बरतने के लिए निर्देश दिए गए।

मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि अकेले बुधवार को कुल 4882 चालान जारी किए गए, जिनमें ज़्यादातर मास्क न पहनने से सम्बन्धित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार द्वारा 'मिशन फतेह' के अंतर्गत गरीबों को 15 लाख मास्क बाँटने का फैसला किया गया है, जिनमें से मौजूदा समय में एक लाख मास्क बाँटे जा रहे हैं, जबकि बाकी के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

पुलिस प्रमुख ने बताया कि मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए जेलों में सैंपल टेस्टिंग के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। डी.जी.पी ने आगे बताया कि पंजाब आने वाले यात्रियों के लिए सोमवार आधी रात से शुरू की गई ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत 31959 रजिस्ट्रेशनें पहले ही हो चुकी हैं, जिनमें से 4277 हॉट-स्पॉट (प्रभावित स्थानों) विशेष तौर पर दिल्ली से सम्बन्धित हैं।

गृह सचिव सतीश चंद्र द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार लॉकडाऊन के उल्लंघन सम्बन्धी प्रवासी मज़दूरों के ख़िलाफ़ की गई एफ.आई.आर ज़ रद्द करने की प्रक्रिया पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी डिप्टी कमिश्नरों और ज़िला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

इससे पहले, कोविड-19 बीमारी के प्रबंधन और जल्दी पता लगाने के लिए रा%य के अंदर शुरू की जा रही रैपिड एंटीजेन टेस्टिंग संबंधी स्वास्थ्य, मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी सलाहकार डा. के.के. तलवाड़ ने कहा कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और पटियाला ज़िलों को पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शिनाख़्त की गई है। इस टैस्ट के द्वारा नतीजे केवल 30 मिनट के समय के दौरान ही प्राप्त हो जाते हैं। निजी अस्पतालों में रेट तय करने सम्बन्धी उन्होंने बताया कि अस्पतालों के साथ पहले दो मीटिंगें हो चुकी हैं और अगली मीटिंग सोमवार को की जानी है, जिसके उपरांत रेट तय किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि चाहे राज्य के अंदर मामलों की गिणती और मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत और कई अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, परन्तु कोविड का फैलाव चिंताजनक है और कुछ सीमित / सूक्ष्म सीमित क्षेत्रों में सामाजिक फैलाव पर रोक भी देखने को मिली है। रा%य के अंदर टेस्टिंग में की गई वृद्धि संबंधी डा. तलवाड़ ने बताया कि 15 ज़िला अस्पतालों (बरनाला, बठिंडा, फाज़िल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, संगरूर, मुक्तसर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना और रोपड़) में ट्रूनैट मशीनें चालू हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी 15 और मशीनों के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनके द्वारा टेस्टिंग 60 मिनटों में हो जाती है।

प्रमुख सचिव डी.के. तिवाड़ी ने बताया कि रा%य के अंदर मौजूदा मृत्यु दर 2.6 फीसदी है, जबकि भारत में यह 2.8 फीसदी है। उन्होंने आगे बताया कि कोविड मरीज़ों में 70.8 फीसदी बिना लक्षण वाले हैं, 14.7 फीसदी कम प्रभावित, 8.8 फीसदी दर्मियाने प्रभावित और 5.6 फीसदी ज़्यादा प्रभावित हैं।

जिलाधीश ने जानबूझ कर अदायगी न करने वाले डिफाल्टरों से रिकवरी तेज़ करने की हिदायत की

जालंधर/नीरज

डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने माल आधिकारियों को हिदायतें की कि जानबूझ कर कई की अदायगी न करने वाले विल्लफुल्ल डिफालटरें से रिकवरी को तेज़ करके अपनी ड्यूटी को पूरी लगन के साथ निभाया जाये।

जिला प्रशासकीय कंपलैक्स जालंधर में रिकवरी, माल रिकार्ड और ई -कोर्ट मैनेजमेट प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि माल विभाग सरकार की आमदन का मुख्य स्रोत है और हम सभी अपनी ड्यूटी पूरी लगन के साथ निभाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि माली बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक यत्न किये जाने की जरूरत है। उन्होनें कहा कि राज्य सरकार के वित्त को बढ़ाने के लिए माल अधिकारियों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।

डिप्टी कमिशनर ने उप मंडल मैजिस्ट्रेटें को रिकवरी के साथ सम्बन्धित मामलों की निगरानी करने के लिए भी कहा जिससे इस प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को बिना किसी देरी के जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होनें कहा कि विल्लफुल्ल डिफालटरें को बिल्कुल सहन न किया जाये और ऐसे लोगों खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि विलफुल्ल डिफाल्टरों से बकाया को जल्द से जल्द रिकवरी को यकीनी बनाया जाये। उन्होनें कहा कि विलफुल्ल डिफालटरें को कानून अपने हाथ में लेने की आज्ञा नहीं दी जायेगी और बकाया राशि की रिकवरी को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाये।

डिप्टी कमिशनर ने उनको मालीया का सारा रिकार्ड अपडेट करने और ई -कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग के साथ लागू करने के लिए कहा।

इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर श्री जसबीर सिंह, उप मंडल मैजिस्ट्रेट श्री राहुल सिंधु, श्री गौतम जय, श्री जे इन्द्र सिंह, श्री वनीत कुमार और अन्य शामिल थे।

डिप्टी कमिशनर ने कृषि विभाग को टिड्डी दल से चौकस रहने की दिए निर्देश

जालंधर/नीरज

डिपटी कमिशनर श्री घनश्याम थोरी ने आधिकारियों को कहा कि वह जिले में टिड्डी दल से किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए पहले से ही पूरे सावधान रहें। जिला प्रशासकीय कंपलैक्स में अलग अलग विभागों के मुखियों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए श्री थोरी ने कहा कि टिड्डीयां नुकसानदेय कीड़े -मकौड़े हैं जो फसलों का भारी नुक्सान कर सकते हैं। उन्होनें कृषि और किसान भलाई विभाग को उप मंडल मैजिस्ट्रेटों की निगरानी में गाँवों में जागरूकता कैंप लगाने के लिए कहा जिससे ज़मीनी स्तर पर जागरूकता फलाई जा सके।

उन्होंने आधिकारियों को कहा कि किसानों को गुरुद्वारों और अन्य के द्वारा संवेदनशील के इलावा वह गाँवों में जागरूकता के लिए जनतक संबोधन प्रणाली का प्रयोग करने और यदि वह टिड्डी दल देखते हैं तो वह जिला प्रशासन को सूचित करे। मुख्य कृषि अधिकारी डा. सुरिन्दर सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से पहले ही गाँवों में जागरूकता गतिविधियां चलाई जा चुकीं हैं, मोक ड्रिल्लज़ की गई हैं और हमलों की स्थिति में तुरंत कार्यवाही के लिए अलग -अलग विभागों की सांझी टीमें भी गठित की गई हैं। डीसी ने कृषि और इसके साथ जुड़े विभागों को जिले के किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल कर निरंतर यत्न करने के लिए भी कहा।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की अंतिम परीक्षाएं रद्द किए जाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे

विद्यार्थियों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब के प्रसंग में ऑन-लाईन विधि उचित नहीं

चंडीगढ़/ब्यूरो

कोविड के कारण पंजाब के अंदर परीक्षाएं लेने के लिए स्थिति अनुकूल न होने का हवाला देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह विद्यार्थियों के हितों और सुरक्षा के लिए यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की परीक्षाओं को रद्द करवाने की माँग सम्बन्धी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यूनिवर्सिटियों / कॉलेजों द्वारा सितम्बर तक लाज़िमी तौर पर अंतिम परीक्षाएं लिए जाने सम्बन्धी 6 जुलाई के गृह मंत्रालय के आदेशों को रद्द करने और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यू.जी.सी) के दिशा-निर्देशों को वापस लिए जाने की माँग करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कोविड मामले रोज़ाना बढ़ रहे हैं और सितम्बर में इसका शिखर होने के अनुमान हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे हालातों में वह विद्यार्थियों के जीवन को जोख़िम में डालने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इन नाजुक हालातों में विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए एकत्र करने का जोख़िम कैसे उठा सकते हैं? उन्होंने आगे कहा कि यू.जी.सी. द्वारा सुझाए गए विकल्प के अनुसार इम्तिहान ऑनलाइन नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि पंजाब में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों में ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास किफ़ायती और निर्विघ्न इन्टरनेट क्नैकटिविटी की पहुँच नहीं है।

उन्होंने इस मामले पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा की गई मीटिंग में ज़ोर देते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में इम्तिहान

करवाना संभव नहीं। तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री के इस विचार कि मौजूदा स्थिति में इम्तिहान सुरक्षित ढंग से नहीं करवाए जा सकते, के साथ पूरी तरह सहमति अभिव्यक्त की।

इस बात पर जोर देते हुए कि इस मामले पर अन्य 7 राज्यों ने पहले ही केंद्र सरकार के पास अपनी, चिंताएं जाहिर की हैं, कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व वाले सभी राज्यों ने इस सम्बन्धी केंद्र सरकार के पास पहुँच करने का फैसला किया

उच्च शिक्षा मंत्री को केंद्र में अपने समकक्ष और उप-कुलपतियों द्वारा यू.जी.सी को लिखने के लिए कहा

था। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री तृप राजिन्दर सिंह बाजवा को भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में अपने समकक्ष को पत्र लिखने के लिए कहा। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के उप कुलपतियों से अपील की कि वह कोविड संकट के मद्देनज़र परीक्षाएं करवाने सम्बन्धी जोख़िम की रौशनी में इम्तिहानों को रद्द करने के लिए यू.जी.सी. को भी लिखें।

शिक्षा सचिव राहुल भंडारी ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि उन्होंने पहले ही यू.जी.सी. के चेयरमैन को 6 जुलाई, 2020 को आखिरी सैमेस्टर की परीक्षाएं करवाने सम्बन्धी जारी किए गए यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों पर फिर विचार करने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा, ''कोविड-19 संकट और रोज़ाना की मरीज़ों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए इम्तिहान करवाने की संभावना दूर-दूर तक संभव नहीं लगती। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों / कॉलेजों के होस्टल खाली करवा लिए गए थे और कोविड केयर सैंटरों के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे और अब तक नियमित रेल / बस सेवाएं चालू नहीं की गई थी, जिससे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देने के लिए आना संभव नहीं लगता।

ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने पिछले सैमेस्टरों की कारगुज़ारी के आधार पर डिग्रियाँ / डिप्लोमे देने और विद्यार्थियों को प्रमोट करने के अपने फ़ैसले का पहले ही ऐलान कर दिया था और अपनी कारगुज़ारी में सुधार करने के इच्छुक विद्यार्थियों को हालात सुखद होने पर परीक्षा देने की आज्ञा दी जाएगी।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.